हस्तक्षेप

सपनों में बनता न्यू इंडिया

मंशा ठीक पर चुनौतियां बड़ीं

www.samaylive.com

राष्ट्रीय सहारा

नई दिल्ली। शनिवार ● 29 जून ● 2019

hastkshep.rsahara@gmail.com

नये अर्थ और नई अपेक्षाएं

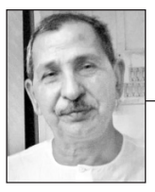

■ प्रो. रामेश्वर मिश्र पंकज

वरिष्ठ लेखक

राजनेताओं को अपने मतदाताओं के सबसे बड़े हिस्से को प्रसन्न करने के लिए सदा ही आकर्षक नारे गढ़ने पड़ते है क्योंकि आधुनिक यूरो अमेरिकी लोकतंत्र लाबी का खेल है। बात तो सब पूरे समाज या राष्ट्र की करते हैं पर इस वयस्क वोट पर आधारित लोकतंत्र में एक मुख्य लाबी या दो-चार बड़ी लाबी पर ध्यान केंद्रित करना प्राथमिकता है। अमेरिका की तंबाकू और शराब की लाबियों के खेल जग जाहिर हैं और उनकी धमक भारत शासन की नीतियों पर साफ दिखती है। तंबाकू पीना जहर है; यह ऐसे भीषण रूप में फैलाया कि कई नीतिगत फैसले लिए गए। शराब पीना उससे बड़ा जहर है पर उसके विरुद्ध वैसा भय नहीं फैलाया गया। इन दिनों एलोपैथी दवाओं की लाबी दुनिया में भयंकर है, जो झूठी महामारियों और हानिकर इंजेक्शन की बिक्री का मकड़जाल फैलती हैं। भारत के अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री इस लाबी की चपेट में हैं। बिहार का चमकी बुखार भी इस लाबी का खेल है।

भारत से इंग्लैंड हटे, इसमें अमेरिका की रंगभेद विरोधी और हिटलर विरोधी लाबी की निर्णायक भूमिका थी जिसका परिणाम अगस्त 1947 में सामने आया। तो न्यू इंडिया शब्द या नारा किस लाबी के लिए है ? मोदी जी बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि 2000 ईस्वी के बाद जन्म लिए बच्चे उनका मुख्य टार्गेट समूह हैं, उनकी भाषा है : न्यू इंडिया । जैसे कम्युनिज्म की ओर आकर्षित धनी लोगों और जमींदारों की भाषा भारत में थी-समाजवाद, समानता, गरीबी हटाओ, औद्योगीकरण आदि। कांग्रेस ने उसे पकड़कर शासन की सीढ़ी बनाया। फिर सरकारी सुविधाओं : संरचनागत ढांचा, लगभग मुफ्त बिजली , पानी, बैंक से सस्ते ऋण, अनेक रियायतों आदि ऐसे एक सरकारी अनुग्रह से धनी बने लोगों को और फैलने के लिए उदारीकरण और वैश्वीकरण के नारे उछाले गए। इसी प्रकार नयी युवा पीढ़ी में आधार बढ़ाने का नारा है : न्यू इंडिया ।

नये नारे के नये मायने

बहरहाल, इस नारे के साथ, वस्तुतः क्या आशाएं हैं? क्या संभावनाए हैं? सबसे पहले तो, यह नयी पीढ़ी को स्वरोजगार में समर्थ बनाएगा। सरकारी नौकरियों के पीछे युवा दौड़ना कम करें, ऐसी नीतियां मोदी सरकार की हैं, स्वरोजगार की अनेक योजनाएं सरकार लायी हैं। इससे राष्ट्र में आत्म विश्वास बढ़ेगा। बेरोजगारी घटेगी। मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, सब इसमें बड़ी सीमा तक सहायक होंगे।

फिर, गरीबी का रोना जाएगा। कांग्रेस ने कम्युनिज्म की सेवा में एक बड़ा झूठ फैलाया : दुनिया में दो ही वर्ग हैं : गरीब और अमीर तथा इनमे अंतर्निहित टकराव है, यह हवा कांग्रेस ने फैलाई। पहले नरेन्द्र मोदी भी इस झूठी नारेबाजी में फंसे थे, अब उनकी नयी भाषा उभरी है। उन्होंने इधर कहा : दो ही वर्ग हैं : एक गरीब, दूसरा जो उनको गरीबी से निकालेगा। इस प्रकार इनमें टकराव नहीं, वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग युद्ध नहीं , परस्परता की भावना लाएंगे नरेन्द्र मोदी। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं : हितों की परस्परता।

मोदी सरकार परस्परता की भावना बढ़ाएगी। परस्पर विद्वेष, टकराव, झगड़े की नहीं। दूसरे, सामाजिक दुर्गुणों के प्रति मोदी जी में सात्विक क्रोध है। अतः छुआछूत, ऊंचनीच की भावना बिदा होगी। इसी प्रकार स्वच्छता की भावना बढ़ती जाएगी। लड़के लड़कियों मे फर्क अतीत की वस्तु हो जाएगी। जो फर्क करेगा, उसकी ओर नयी पीढ़ी अजूबे की तरह देखेगी। चयन की विविधता से लोगों को आत्मगौरव और सार्थकता की अनुभूति होगी। अतः सीमित विकल्पों से उपजने वाली होड़ और प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी । मन बड़ा होगा और कार्य के अवसर विविध होंगे।

जो होता दिख रहा है

देशभक्ति की भावना का जैसा तीव्र विकास हो रहा है और रक्षा जरूरतों की जैसी चिंता मोदी सरकार कर रही है, उनके चलते सैन्य क्षेत्र में हम एक बड़ी शक्ति होंगे। इससे हमारा मान बढ़ेगा और सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट भी निश्चित है। पाकिस्तान यदि टूटा तो बालूचों, पश्तूनों और सिंधियों के लिए नयी पीढ़ी में सहज आत्मीयता है। अतः ये समाज हिंदुओं से प्रेम करेंगे जो राष्ट्र की बड़ी शक्ति होगी । अफगानों से दोस्ती चल ही रही है, जो बढ़ेगी। इस प्रकार एक बड़ा शांति क्षेत्र और बड़ा आर्थिक क्षेत्र तथा एक बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र यह घोषित हो सकता है जो विश्व परिदृश्य को बदल देगा।

नदियों को जोड़ने का काम पूरा होने पर सूखा और बढ़ पर लगभग पूर्ण नियंत्रण संभव हो जाएगा। अच्छी सड़कें यातायात और व्यापार के लिए बहुत उपादेय होंगी, जिससे समृद्धि आएगी। आय कर चोरी रुक जाएगी और बेनामी संपत्तियां नहीं होंगी। सबके पास अपने आवास होंगे। हर गांव तक बिजली पहुंच जाएगी। यह सब वादे के स्तर पर नहीं वस्तुतः होते दिख रहे हैं।

सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात अंत में : नरेन्द्र मोदी जी ने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात राष्ट्रपति महोदय को कृतज्ञता ज्ञापन में दिये गए वक्तव्य में कही है : कि चुनावों में किसे कितनी सीट मिली, इसे लेकर राग द्वेष पालते बैठने का यह समय नहीं है। प्रत्येक जन प्रतिनिधि महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि हम सब 130 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के नाते यहां हैं। यह बहुत सही और बहुत बड़ी बात है। यह संविधान की मूल बात है जिसमें भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें हर विचार को समान महत्त्व प्राप्त है और प्रत्येक व्यक्ति को विचार सामर्थ्य से सम्पन्न माना गया है। आपातकाल में राज्य को सोशलिस्ट घोषित कर इसे एक क्षुद्र राजनीतिक विचार से बांधकर सिकोड़ दिया गया। क्यों भाई, मैं समाजवाद का प्रचंड विरोधी हूं और मैं एक दार्शनिक हूं, बहुत अध्ययन करने वाला हूं और खूब सोचविचार कर राष्ट्र भक्ति की भरपूर भावना से समाजवाद का विरोध राष्ट्र हित में कर रहा हूं तो मूल संविधान तो मुझे पूर्ण अधिकार देता है पर आपातकाल

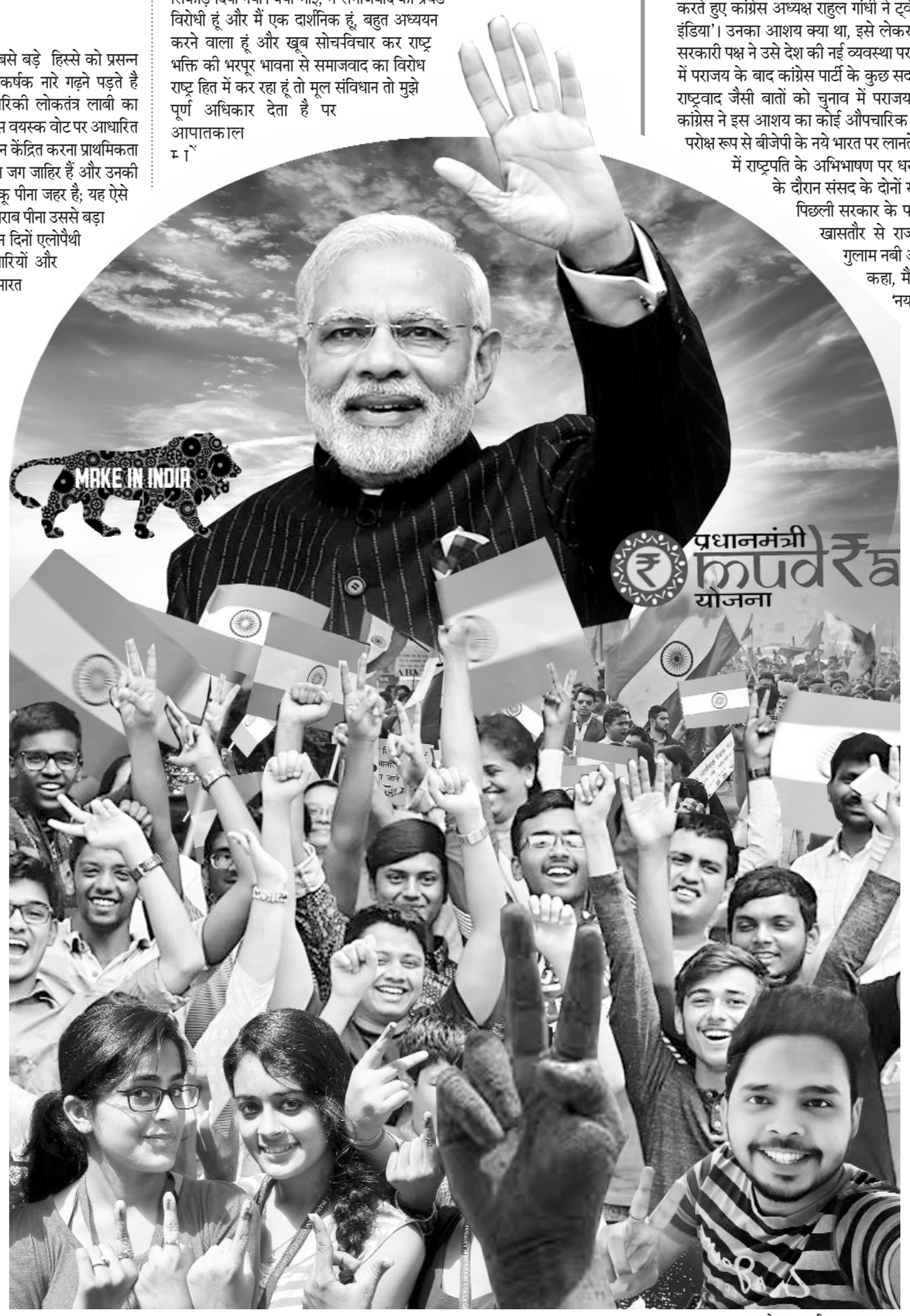

इलस्ट्रेशन : रवीन्द्र कुमार दास

मोदी सरकार परस्परता की भावना बढ़ाएगी। परस्पर विद्वेष, टकराव, झगड़े की नहीं। दूसरे, सामाजिक दुर्गुणों के प्रति नरेन्द्र मोदी में सात्विक क्रोध है। अतः छुआछूत , ऊंच-नीच की भावना विदा होगी। इसी प्रकार, स्वच्छता की भावना बढ़ती जाएगी। लड़के-लड़कियों में फर्क अतीत की वस्तु हो जाएगी। जो फर्क करेगा, उसकी ओर नयी पीढ़ी अजूबे की तरह देखेगी। चयन की विविधता से लोगों को आत्मगौरव और सार्थकता की अनुभूति होगी। अतः सीमित विकल्पों से उपजने वाली होड़ और प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। मन बड़ा होगा और कार्य के अवसर विविध होंगे

संशोधित संविधान मुझे यह अधिकार नहीं देता। यह तो मूल संविधान की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या है।इसके कारण समाजवाद के समर्थक संसद सदस्य तो श्रेष्ठ हैं और उसे एक पाप पूर्ण विचार बताने वाले सांसद हीन कोटि के हैं, ये क्या बात हुई? आशा है प्रधानमंत्री के विचारों के प्रकाश में न्यू इंडिया इस वैचारिक नस्लवाद को समाप्त कर मूल संविधान की भावना के अनुरूप सच्चे अर्थ में लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा।

अब कुछ चिंतनीय बातें। प्रशासन में मुस्लिम युवाओं को जैसे बढ़ावा मिल रहा है, अगर मुसलमानों में स्वयम को ही मोमिन और बाकी सबको काफिर अतः नष्ट करने योग्य मानने के विरुद्ध कोई बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन नहीं चला तो ये मुस्लिम प्रशासक राष्ट्र तोड़क हो सकते हैं क्योंकि 1860 से 1947 तक का ट्रक रेकॉर्ड यह बताता है। बहुत बड़े दंगे भड़काए जा सकते हैं, जिनसे भारी जनध्वन हानि होगी। नशेबाजी और तस्करी बढ़े तो और भी भयावह परिणाम संभव हैं। पर इसे न्यू इंडिया का भाग नहीं कहा जा सकता। यह तो ओल्ड इंडिया का हैंग ओवर कहा जाएगा ।

■

कांग्रेस का नया गीत 'कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन'

■ प्रमोद जोशी

वरिष्ठ पत्रकार

अचानक 'न्यू इंडिया' शब्द विवाद के घेरे में आ गया है। हाल में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सेना की 'डॉग यूनिट' के कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें शेयर करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा, 'न्यू इंडिया'। उनका आशय क्या था, इसे लेकर अपने-अपने अनुमान हैं, पर सरकारी पक्ष ने उसे देश की नई व्यवस्था पर तंज माना। लोक सभा चुनाव में पराजय के बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने देशद्रोह, राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रवाद जैसी बातों को चुनाव में पराजय का कारण माना। हालांकि कांग्रेस ने इस आशय का कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, पर परोक्ष रूप से बीजेपी के नये भारत पर लानतें जरूर भेजी जा रही हैं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चली बहस के दौरान संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के सदस्यों ने पिछली सरकार के पांच साल पर निशाना लगाया। खासतौर से राज्य सभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 'नया भारत' आप अपने पास रखें और हमें हमारा 'पुराना भारत' दे दें, जहां प्यार और भाईचारा था। जब मुस्लिम और दलित को चोट पहुंचती थी, तब हिंदुओं को पीड़ा का अहसास होता था और जब हिंदुओं की आंखों में कुछ पड़ जाता था तब मुस्लिमों और दलितों की आंखों से आंसू निकल जाते थे।

नया भारत पर...

गुलाम नबी आजाद ने कहा, 'झारखंड लिंचिंग और हिंसा की फैक्टरी बन गया है। हर सप्ताह यहां दलित और मुस्लिम मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री 'सबका साथ सबका विकास' की लड़ाई में हम आपके साथ हैं, लेकिन यह जनता को दिखना चाहिए। हम इसे कहीं नहीं देख सकते हैं। नये भारत में लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। आप जंगल में जानवरों से नहीं डरेंगे मगर कॉलोनी में मनुष्यों से डर जाएंगे। हमें वह भारत दे दो जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक दूसरे के लिए जीते हैं। इस 'पुराने भारत' की पुकार पर नरेन्द्र मोदी ने मौका लगते ही प्रहार किया। उन्होंने कहा, वे 'पुराना भारत' वापस चाहते हैं, जिसमें कैबिनेट के प्रस्ताव को प्रेस कांफ्रेंस में फाड़कर फेंक दिया जाता है। जहां नौसैनिक पोत का इस्तेमाल निजी यात्राओं के लिए होता था, जहां 'टुकड़े-टुकड़े' गिरोह का समर्थन किया जाता था। हाल में कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर रचित सेठ ने अपने एक ब्लॉग में लिखा कि कांग्रेस के पराभव के लिए वामपंथी झुकाव वाले सहायक जिम्मेदार हैं। पोस्ट के प्रकाशन के कुछ समय बाद ही इसे हटा लिया गया, पर उतनी देर में ही यह चर्चा का विषय बन गई। इससे इतना जाहिर हुआ कि जो बात बाहर कही जा रही थी, वह भीतर भी चल रही है।

दंगों का पुराना फसाना

कांग्रेस की यह लाइन आज पहली बार सामने नहीं आई है। इसका विकास पिछले पांच साल में भी नहीं हुआ है, बल्कि यह बीजेपी के उदयकाल से ही चल रही है। नब्बे के दशक में जब आजादी के बाद दूसरी बार कांग्रेस सत्ताच्युत हुई, उसने अपने पुराने भारत का हवाला देना शुरू कर दिया। बेशक विचारधारा के स्तर पर कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले बेहतर धरातल पर खड़ी है, पर ऐसा नहीं है कि उसके कार्यकाल में मलियाना और भागलपुर जैसे प्रसंग नहीं हुए हों। सन 1984 सबसे बड़ा कलंक है। यों भी अस्सी के उत्तरार्ध तक देश में ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकारें ही रहीं। सन 2012 में आरटीआई के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि 1984 से लेकर 2012 तक सिर्फ एक साल ऐसा गुजरा, जिसमें 500 से कम दंगे हुए और इसमें 100 से कम लोगों की मौत हुई। इन 28 साल में देश में दंगों की कुल 26817 वारदातें हुई हैं, जिनमें 12902 लोगों ने जान गंवाई। ये सरकारी आंकड़े हैं। वास्तव में मरने वालों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इन 28 साल में से 18 साल देश पर कांग्रेस का राज रहा। इस दौरान कुल 8619 लोगों ने दंगों में जान गंवाई यानी औसतन हर साल 478 लोग दंगों में मारे गए। वहीं दस साल गैरकांग्रेसी शासन रहा, जिस दौरान 4283 लोग दंगों में मारे गए यानी हर साल औसतन 428 लोगों की दंगों में मौत हुई। दंगों के आंकड़े कुछ नहीं कहते, सिवाय इसके कि वे हमारे सामाजिक अंतर्विरोधों और प्रशासनिक अकुशलता की कहानी कहते हैं। उससे भी ज्यादा वे राजनीतिक मौकापरस्ती के प्रतीक हैं। यह सवाल अपनी जगह है कि किस पार्टी की भूमिका कम और ज्यादा है। पर कांग्रेस के सामने ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा है? बीजेपी का 'नया भारत' उसे नामंजूर है, तो इसमें हैरत नहीं। पर जिस 'पुराने भारत' को वापस लाना चाहती है, वह क्या है? लोक सभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी हार के कारणों पर शायद अभी विचार नहीं किया है। वह विचार आंतरिक स्तर पर होगा और जरूरी नहीं कि सारी बातें सामने आएं, पर पार्टी को जनता के सामने ईमानदारी से अपने दोषों को स्वीकार करना होगा। उसे यह बताना होगा कि जनता ने उसे अस्वीकार क्यों किया। वर्ना यही माना जाएगा कि गलती कांग्रेस की नहीं जनता की है।

क्यों फेल हुई रणनीति?

दिसम्बर, 2018 में यानी लोक सभा चुनाव के ठीक पहले हुई कांग्रेस महासमिति की हुई में दिए गए बयानों और पास किए गए प्रस्तावों पर नजर डालें तो नजर आता है कि पार्टी व्यक्तिगत रूप से नरेन्द्र मोदी पर हमलों को अपनी रणनीति बनाएगी। राफेल मामले को उठाने के बाद राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' नारा दिया था। महासमिति के अधिवेशन में सोनिया गांधी ने 'अहंकार मुक्त भारत' बनाने का आह्वान किया। पर यह फौरी टैक्टिक्स थी, दीर्घकालीन विचारधारा नहीं। ज्यादा बड़ा सवाल था कि कांग्रेस किस विचार की जमीन पर खड़ी है और वह देश को क्या संदेश देना चाहती है? उत्तर के तीन राज्यों में कांग्रेस ने खेती से जुड़े संकट को निशाना बनाया था। इसके अलावा उसने नौजवानों की बेरोजगारी और छोटे व्यापारियों और लघु उद्यमियों की परेशानियों को लक्ष्य किया, जिसमें जीएसटी और नोटबंदी शामिल हैं। खेती की समस्या का उसका समाधान है कर्जमाफी। पता नहीं, देश के औद्योगीकरण और आर्थिक विकास का क्या कार्यक्रम उसके पास है? गुलाम नबी आजाद ने जिस पुराने भारत को वापस पाने की इच्छा व्यक्त की है, क्या उसके लिए उन्हें नरेन्द्र मोदी से याचना करनी होगी? उनके इस अनुरोध को तो वोटर ही पूरा करेगा? उन्हें केवल अपनी परिकल्पना की श्रेष्ठता को साबित करना है। यदि जनता को उनपर भरोसा नहीं है, तो दोष किसका है? क्या पार्टी के पास दूरदृष्टि है? क्या पार्टी ने क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत नेताओं को बढ़ावा दिया है? क्या उसके पास आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने की योजना है? बेहतर हो कि अब जल्द से जल्द कांग्रेस महासमिति की बैठक फिर से बुलाई जाए और पार्टी अपनी पराजय के कारणों पर आत्ममंथन करे। पिछले चुनाव में उसकी परीक्षा हो चुकी है। अब अगली परीक्षा पांच साल बाद है।

झारखंड लिंचिंग और हिंसा की फैक्टरी बन गया है। हर सप्ताह यहां दलित और मुस्लिम मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री 'सबका साथ सबका विकास' की लड़ाई में हम आपके साथ हैं, लेकिन यह जनता को दिखना चाहिए। हम इसे कहीं नहीं देख सकते हैं। नये भारत में लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। आप जंगल में जानवरों से नहीं डरेंगे मगर कॉलोनी में मनुष्यों से डर जाएंगे। हमें वह भारत दे दो जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक दूसरे के लिए जीते हैं

राष्ट्रवाद और...

कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान, कश्मीर, नक्सलपंथियों और कुल मिलाकर राष्ट्रवाद के बारे में अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करना होगा। सन 2012 में राहुल गांधी ने खुद पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का श्रेय इंदिरा गांधी को दिया था। एक तरफ कांग्रेसी इंदिरा गांधी की तारीफ इस बात के लिए करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, वहीं दूसरी तरफ वे पुलवामा से लेकर बालाकोट के प्रसंग पर अंतर्विरोधी बातें करते हैं। राहुल गांधी के ट्वीट में तंज था या नहीं था, यह अलग बात है, पर उसके केंद्र में भारतीय सेना थी। इसे 'आ बैल मुझे मार' की श्रेणी में क्यों न रखा जाए? एक बात साफ है कि पाकिस्तान के प्रति नरमी की नीति सामान्य नागरिक को पसंद नहीं है। पार्टी नेतृत्व चाहे तो अपने सामान्य कार्यकर्ता से पूछना चाहिए कि देशप्रेम और राष्ट्रभक्ति के बारे में उसकी राय क्या है, जवाब मिल जाएगा। पाकिस्तान के बारे में सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता की वही राय मिलेगी, जो सामान्य जनता की राय है। नवजोत सिंह सिद्धू और मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं की राय अपने शिखर नेताओं की राय पर आधारित होती है।

अल्पसंख्यक माने केवल मुसलमान?

दूसरा सवाल कांग्रेस की हिंदू छवि को लेकर है। मई 2014 में लोक सभा चुनाव की पराजय के बाद कांग्रेस पार्टी ने आत्ममंथन शुरू किया। जून में वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि 'छद्म धर्मनिरपेक्षता' और अल्पसंख्यकों के प्रति झुकाव रखने वाली छवि को हमें सुधारना होगा। फिर दिसम्बर में खबर आई कि राहुल गांधी ने पार्टी के महासचिवों से कहा है कि वे कार्यकर्ताओं से संपर्क करके पता करें कि क्या हमारी छवि 'हिंदू विरोधी' पार्टी के रूप में देखी जा रही है? इसके बाद गुजरात विधानसभा के चुनाव के पहले राहुल गांधी ने मंदिरों की यात्रा शुरू की। लोक सभा चुनाव के दौरान सॉफ्ट हिंदुत्व की कहानियां सुनाई पड़ रही थीं। पर कुल मिलाकर सब कुछ संशय से भरा था। हिंदू छवि को लेकर स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस के भीतर लगातार टकराव चलता रहा है, जिसकी शुरुआत पुरुषोत्तम दास टंडन और जवाहर लाल नेहरू के टकराव से हुई थी। हिंदू छवि की अवहेलना और मुस्लिम कट्टरपंथ के तुष्टीकरण की नीति को लेकर पार्टी के भीतर आज की बहस नहीं है। हाल में रशीद किदवई ने अपने लेख में नब्बे के दशक में कांग्रेस के प्रवक्ता रहे वीएन गाडगिल के एक बयान को उद्धृत किया है। उन्होंने कहा, 'जैसे ही शाही इमाम कोई बात कहते हैं पार्टी ऐसे व्यवहार करती है गोया ईश्वर ने कुछ कह दिया है। क्या अल्पसंख्यक माने सिर्फ मुसलमान हैं? बौद्ध और सिख नहीं? जब कश्मीर में 36 सिख मारे गए, एक भी कांग्रेसी ने शोक प्रकट नहीं किया। जम्मूकश्मीर में एक भी बौद्ध राज्य सचिवालय में काम नहीं कर रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से चुने गए एकमात्र बौद्ध कर्मचारी को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए धर्मांतरण करना पड़ा। कांग्रेस इस पर खामोश रही।' ये बातें कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कही थी। यह केवल उनके मन की बात नहीं रही होगी। ■

पेज 2 एस.पी.शर्मा। राजीव सिंह। सत्येन्द्र प्रसाद सिंह

पेज 3 हितेन्द्र पटेल। सन्नी कुमार। शान कश्यप

पेज 4 राजेंद्र शर्मा। कुमार नरेन्द्र सिंह। अवधेश कुमार